

## अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता और सर्वोच्च न्यायालय

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत कनौजिया नामक पत्रकार को जमानत पर तुरंत रहिा करने का आदेश देते हुए कहा कि पत्रकार ने किसी व्यक्तिकी स्वतंत्रता को बाधति करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कथिा थिा ।

### प्रमुख बदिु

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो संविधान द्वारा संचालति है । इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्रकार द्वारा कथिा गया ट्वीट नदिनीय है, लेकनि उसकी गरिफ्तारी और उत्पीड़न द्वारा उस व्यक्तिके मौलिक अधिकारों के हनन कथिा गया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को 'स्वतंत्रता से वंचति करने का भयावह मामला' बताया ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मुक्त भाषण और आलोचना को अव्यवस्था के नाम पर प्रतिबंधति नहीं कर सकते । सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में यह साफ कथिा कि पत्रकार की रहिाई को उसके ट्वीट के समर्थन के तौर पर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के सर्वोच्च संरक्षक की भूमिका के रूप में देखा जाना चाहति है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि कनौजिया के मामले में कानून के आधार पर प्रकरथिा का पालन करते हुए एवं मुख्य न्यायिक मजस्ट्रेट की शर्तों पर याचिकाकर्त्ता के पतिा (कनौजिया) को तुरंत जमानत पर रहिा कथिा जाए ।
- उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि कनौजिया के खलिाफ 'व्यक्तगत प्रतिशोध' के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी ।
- भारतीय दंड संहतिा (Indian Penal Code) की धारा 505 (सार्वजनिक दुरव्यवहार की नदिा करने वाले बयान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम (Information Technology Act) की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत गरिफ्तारी के लथिि असाधारण कारण लखति रूप में अपेक्षति हैं ।

### पृष्ठभूमि

- प्रशांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदतियनाथ पर एक आपत्तजनिक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कथिा थिा ।

### मुक्त भाषण या अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लखति और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदत्त है कतिु इन अधिकारों को नमिनलखति स्थतियिों में बाधति कथिा जा सकता है-
- भारत की एकता, अखंडता एवं संपरभुता पर खतरे की स्थति, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव, न्यायालय की अवमानना
- भारत के सभी नागरिकों को वचिार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियिों के वचिारों के प्रचार की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) प्राप्ति है । प्रेस/पत्रकारतिा भी वचिारों के प्रचार का एक साधन ही एक साधन है इसलथिि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मलति है ।

### बंदी प्रत्यक्षीकरण

### What is Habeas Corpus?

- हालिया प्रकरण में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की गई थी ।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत रटि जारी करने का अधिकार होता है ।
- 'Habeas Corpus' लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ 'को प्रस्तुत किया जाए' होता है ।
- यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है, जिसे दूसरे द्वारा हरिसत में रखा गया है । यह किसी व्यक्ति को जबरन हरिसत में रखने के विरुद्ध होता है ।

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रटि सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है ।

बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं की जा सकती है?

- अगर व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हरिसत में लिया गया हो ।
- यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो ।
- न्यायालय के आदेश द्वारा हरिसत में लिया गया हो ।

स्रोत- दृष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-orders-immediate-release-of-journalist-prashant-kanojia-on-bail>

